



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए 3-16-2019-1-पांच (31).—

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर राज्य कर को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से लगाया जाएगा, यथा:-

सारणी

आपूर्ति का विवरण	दर (प्रतिशत)	शर्तें
(1)	(2)	(3)
किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल को या उसके पश्चात पचास लाख रुपए तक के सकल कारोबार तक माल या सेवाओं या दोनों की जाने वाली प्रथम आपूर्ति	3	<p>1. आपूर्ति ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाती हो, -</p> <p>(i) जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार पचास लाख रुपए या इससे कम रहा हो;</p> <p>(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के पात्र न हों;</p> <p>(iii) जो ऐसी किसी आपूर्ति में संलग्न न हों जिन पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर न लगाया जाता हो;</p> <p>(iv) जो कि किसी प्रकार के अंतर्राज्यीय बाह्य आपूर्ति में संलग्न न हों;</p> <p>(v) जो कि न तो नैमित्तिक कर दाता हों और न ही कर देने वाले अनिवासी व्यक्ति हों;</p> <p>(vi) जो कि ऐसे इलैक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने में संलग्न न हों जो कि धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित हो; और</p> <p>(vii) जो कि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न न हों जिनका विवरण नीचे दिए गए अनुबंध के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त अनुबंध के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उक्त शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों।</p> <p>2. जहां कि एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति के पास वही परमानेंट एकाउंट नंबर हो जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत जारी किया गया हो, वहां ऐसी आपूर्तियों पर राज्य कर का भुगतान ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा इस अधिसूचना के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर से किया जाता हो।</p> <p>3. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा की गई आपूर्ति के प्राप्तकर्ता से न तो किसी कर की वसूली करेगा और न ही वह किसी प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा।</p> <p>4. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) में यथा संदर्भित आपूर्ति बिल, टैक्स इनवायस के स्थान पर, जारी करेगा और इसमें राज्य माल और सेवा कर नियमावली के नियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे भी दिए जाएंगे।</p>

5. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति आपूर्ति बिल के शीर्ष पर निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख करेगा, यथा:- 'इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13-14/2011 के अन्तर्गत 17/05/2019 के अनुसार कर का भुगतान करने वाला करदाता व्यक्ति, जो कि आपूर्ति पर कर की वसूली करने के लिए पात्र नहीं है'.

6. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान के विकल्प का चयन करता है वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 1 (1) या धारा 11 के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के बावजूद कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट सभी बाह्य आपूर्तियों पर तीन प्रतिशत के दर से राज्य कर का भुगतान करने का दायी होगा।

7. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान का विकल्प का चयन करता है वह उस अंतः आपूर्ति पर राज्य कर का भुगतान करने का दायी होगा जिस पर वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) या, जैसी भी स्थिति हो उप धारा (4) के अंतर्गत कर के भुगतान का दायी होता हो।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के उद्देश्य से इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण किए जाने हेतु "वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्रथम आपूर्ति" की अभिव्यक्ति में वे आपूर्तियां आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष के पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की होंगी जिस तारीख से वह व्यक्ति, पंजीकरण कराए जाने

का पात्र बन जाता हो लेकिन इस अधिसूचना के अंतर्गत देय कर के निर्धारण के उद्देश्य में ऐसी आपूर्तियां नहीं आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की हों जिस तारीख से वह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का पात्र बनता हो।

अनुबंध		
क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस-क्रीम और अन्य खादय बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति की पात्रता के निर्धारण के लिए सकल कारोबार की गणना में ब्याज या बट्टा के माध्यम से अभिव्यक्त प्रतिफल की जहां तक बात हो वहां तक जमा, ऋण या अग्रिम को देकर छूट प्राप्त सेवाओं की की जाने वाली आपूर्ति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

3. स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य से-

(i) "टैरिफ मद", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय का है।

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स तथा सामान्य स्पष्टीकरण नोट्स भी जैसी भी स्थिति हो, शामिल हैं, कि व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भी लागू होंगे।

4. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ ए-3-16-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-16-2019-1-पांच (31), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

F A-3-16-2019-1-V(31)

Bhopal, the 17th May 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (herein after referred to as the "said Act"), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the state tax, on the intra-State supply of goods or services or both as specified in column (1) of the Table below, shall be levied at the rate specified in the corresponding entry in column (2), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (3) of the said table below, namely:-

Table

Description of supply	Rate (per cent.)	Conditions
(1)	(2)	(3)
First supplies of goods or services or both upto an aggregate turnover of fifty lakh rupees made on or after the 1 st day of April in any financial year, by a registered person.	3	1. Supplies are made by a registered person, - (i) whose aggregate turnover in the preceding financial year was fifty lakh rupees or below; (ii) who is not eligible to pay tax under sub-section (1) of section 10 of the said Act; (iii) who is not engaged in making any supply which is not leviable to tax under the said Act; (iv) who is not engaged in making any inter-State outward supply; (v) who is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person; (vi) who is not engaged in making any supply through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52; and (vii) who is not engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Annexure below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said annexure.

2. Where more than one registered person are having the same Permanent account Number, issued under the Income Tax Act, 1961(43 of 1961), state tax on supplies by all such registered persons is paid at the rate specified in column (2) under this notification.

3. The registered person shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.

4. The registered person shall issue, instead of tax invoice, a bill of supply as referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said Act with particulars as prescribed in rule 49 of Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules.

5. The registered person shall mention the following words at the top of the bill of supply, namely: - 'taxable person paying tax in terms of this department notification No. FA-6/2019/37 dated 17/05 2019, not eligible to collect tax on supplies'.

6. The registered person opting to pay state tax at the rate of three percent under this notification shall be liable to pay state tax at the rate of three percent on all outward supplies specified in column (1) notwithstanding any other notification issued under sub-section (1) of section 9 or under section 11 of said Act.

7. The registered person opting to pay state tax at the rate of three percent under this notification shall be liable to pay state tax on inward supplies on which he is liable to pay tax under sub-section (3) or, as the case may be, under sub-section (4) of section 9 of said Act at the applicable rates.

Explanation.-For the purposes of this notification, the expression "first supplies of goods or services or both" shall, for the purposes of determining eligibility of a person to pay tax under this notification, include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for

		registration under the said Act but for the purpose of determination of tax payable under this notification shall not include the supplies from the first day of April of a financial year to the date from which he becomes liable for registration under the Act.
--	--	---

ANNEXURE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

2. In computing aggregate turnover in order to determine eligibility of a registered person to pay state tax at the rate of three percent under this notification, value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

3. *Explanation.* -For the purpose of this notification, -
(i) "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.